सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 18 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 168, पृष्ठः 8+4

इनसाइड तेल से भरा टैंकर पलटा, हादसा टला... » Pg 08

आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं युद्ध की तरह देखता है भारत : मोदी

» Pg 12

फास्टैग : 15 अगस्त से बदल जाएंगे नियम

3000 में बनेगा एक साल के लिए पास

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है। केंद्र सरकार आगामी 15 अगस्त से फास्टैग के नियम में बदलाव करने जा रही है। सरकार की इस पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक साल तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सालाना पास के लिए एक्टिवेशन या रिन्युल के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और एनएचएआई/ एमओआरटीएच की वेबसाइट्स पर अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल-सुगम होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति 60 किमी के दायरे में स्थित टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को खत्म कर एक आसान ट्रांजैक्शन के जरिये टोल पेमेंट को सहज बनाएगी।

फास्टैग क्या है ?

फास्टैग एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे टोल का पेमेंट सीधे उससे जुड़े प्रीपेड खाते से किया जा सकता है। यह आपके वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका होता है और आपको नकद लेन-देन के लिए रुके बिना टोल प्लाजा से गुजरने में सक्षम बनाता है। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार टैग को रिचार्ज/टॉप अप करना होता है।

फास्टैग के फायदे

फास्टैग केइस्तेमाल पर ग्राहक को अपने टैग खाते में किए गए सभी लेन-देन के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट मिलते हैं। ग्राहक को टोल भुगतान के लिए नकदी ले जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राहक डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए अपने टैग खाते को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक FASTag ग्राहक पोर्टल पर अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं।

जंगलचट्टी के पास भूस्खलन चपेट में आए पांच मजदूर

खाई में गिरने से दो की मौत, तीन घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मागज पर पांच मजदूरों के खाई में गिरने की खबर सामने आई है। हादसे में दो की जान चली गई है। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगलचट्टी के पास बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने के चलते पांच मजदूर इसकी चपेट में आकर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में दो की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक जम्मू निवासी थे जोकि डंडी-कंडी संचालन का काम करते थे। जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पहाड़ी पर भूस्खलन की वजह से यह घटना हुई। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफकी टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया।घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

इसमें नितिन कुमार पुत्र रावेल सिंह जिला डोडा जम्मू कश्मीर (पालकी मजदूर) उम्र 18 वर्ष। और चंद्रशेखर जिला डोडा जम्मू कश्मीर (पालकी मजदूर) की मौत हो गई और संदीप कुमार पुत्र दया कृष्णा ग्राम गली तहसील जिला डोडा जम्मू (पालकी मज़दूर), आकाश चितरीय पुत्र दामोदर दास निवासी भावनगर गुजरात, नितिन मन्हास पुत्र मनजीत जिला डोडा जम्मू (पालकी मजदूर), घायल है।

बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानसून की बारिश जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही 19 जून को प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्जना और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। अन्य पहाड़ी जिलों में भी तेज गर्जन और हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। 23 जून तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा।

बुलंदशहर हादसा

सात माह पहले हुई थी तंजील-निदा की शादी, झपकी आने से हुआ हादसा

मासूम समेत पांच जिंदा जले...खाक हो गईं खुशियां

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बदायूं। बदायूं के सहसवान क्षेत्र के निवासी तंजील अहमद अपने चाचा की शादी के बाद परिवार सहित कार से दिल्ली जा रहे थे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में उनकी कार पुलिया से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। तंजील समेत पांच लोगों की मौत हो गई। तंजील की शादी 7 माह पहले हुई थी।

बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह हुए कार हादसे में तंजील अहमद समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों की जलकर मौत हो गई। बदायूं के सहसवान में चाचा की शादी में शामिल होकर परिवार कार से वापस दिल्ली जा रहा था। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह कार पुलिया से टकराकर पलट गई। इससे कार में आग लग गई। हादसे में तंजील, उनकी पत्नी निदा, बहनोई जुबैर, बहन मोमिन व दो साल का भांजा जैनुल की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में छोटी बहन गुलनाज गंभीर रूप से झुलसी है, जिसका इलाज चल रहा है। इस हादसे में तीन परिवारों की खुशियां खाक हो गईं।

सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव हमूपुर चमरपुरा निवासी तंजील अहमद उर्फ लल्ला दिल्ली के मालवीयनगर में पत्नी निदा व पिता तनवीर अहमद के साथ रहते थे। पास में ही सहसवान निवासी उसके बहनोई जुबैर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह रंगाई-पुताई के ठेकेदार थे। गांव हमूपुर चमरपुरा में तंजील के चाचा अलीम की शादी थी। 16 जून को तंजील पत्नी निदा, बहन मोमिन, बहनोई जुबैर व दो साल के भांजे जैनुल को साथ लेकर कार से शादी में शामिल होने गांव आए थे। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद रिश्तेदार अपने-अपने घर चले गए। बुधवार तड़के चार बजे तंजील परिवार संग दिल्ली जाने को कार से निकले। कार वह खुद ही चला रहे थे।

आग का गोला बन गई कार

परिजनों ने बताया कि सभी लोग खुशी-खुशी यहां से रवाना हुए थे। क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। तंजील अहमद बबराला व अनूपशहर-बुलंदशहर होते हुए दिल्ली के लिए जा रहे थे। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव चांदोक फैमिली रेस्टोरेंट के निकट तंजील अहमद को झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर पुलिया व डिवाइडर से टकरा गई। कार पलट गई और उसमें आग लग गई। देखते ही देख कार आग का गोला बन गई।

जिले का लेखपाल संघ चुनाव संपन्न ---

मोहित सचान बने लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष

» कांटे की टक्कर में प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर मारी बाजी

» सुजीत कुशवाहा को मिला जिला मंत्री पद,भारी मतों से दर्ज कराई जीत

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। कानपुर नगर जिले के लेखपाल संघ चुनाव ने इस बार दिलचस्प मोड़ लिया। अध्यक्ष पद की दौड़ में ज़ोरदार मुकाबले के बाद मोहित सचान ने नरेंद्र तिवारी को बेहद कम अंतर से शिकस्त दी। मोहित को जहां 86 वोट मिले, वहीं नरेंद्र तिवारी 81 वोट पाकर महज़ 5 मतों से पीछे रह गए। दूसरी ओर जिला मंत्री पद पर सुजीत कुशवाहा ने एकतरफा जीत हासिल की। उन्हें 149 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी के.के. मिश्रा 103 वोटों पर ही सिमट गए। चुनाव परिणामों के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। फूल-मालाओं और नारों के बीच मोहित सचान व सुजीत कुशवाहा ने साथियों का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि लेखपालों की आवाज़ को कतई दबने नहीं दिया जाएगा। उनकी हर समस्या अधिकारियों के सामने बुलंदी से रखी जाएगी।

सूत्रों की मानें तो यह चुनाव केवल पद नहीं बल्कि संगठन के भीतर नई दिशा और सोच की लड़ाई भी थी,और इस बार बदलाव ने बाज़ी मारी।

अब अधिकारी नहीं बना पाएंगे अनावश्यक दबाव : जिलाध्यक्ष

नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मोहित सचान ने स्वराज इंडिया से बातचीत में बताया कि किसी भी संगठन में पदाधिकारी का रोल बहुत अहम होता है। संगठन का नेतृत्वकर्ता यदि अपने सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ा होता है तो अधिकारी अनावश्यक दबाव नहीं बना पाते हैं। और कर्मचारी को बेहतर माहौल में काम करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर संघ के सदस्यों के साथ बैठक करके उनकी समस्याएं सुनेंगे। जहां कहीं पर जरूरत समझेंगे वहां पर अधिकारियों से वार्ता करके उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। कहा कि जिस तरह से संगठन में अलग तरह का बदलाव हुआ है और लम्बे समय से पदों पर कब्जा जमाए लोग बाहर हुए हैं। उससे पूरी तरह स्पष्ट है कि लोग काम करने की शैली में बदलाव चाहते हैं। और यह बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा।

बिल्हौर तहसील लेखपाल संघ के पूर्व अध्यक्ष ललित चौधरी, सदा ब्रज बिहारी ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया।

ने बताया फूलबाग बाल भवन में लेखपाल संघ का चुनाव शांति पूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष व जिला महामंत्री को बधाई दी।उधर जीत की खुशी में लेखपाल सुनील तरीके से संगठन का पदाधिकारी बनने के बाद तेजतर्रार और युवा मोहित सचान ने जिले के चुनाव में अपनी धाक जमाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं। वह एक एक वोटर से सीधे संपर्क करके अपनी बात रख रहे थे। यही वजह रही कि उनकी रणनीति के आगे प्रतिद्वंदी खेमा शिकस्त खा गया।

कुछ महीने पहले ही बिल्हौर में दर्ज कराई थी जीत

बिल्हौर तहसील में महज कुछ महीने पहले हुए चुनाव में अपनी कुशल बातचीत और काम करने के

शादी से महज 18 दिन बाद नवविवाहिता के साथ गैंगरेप, हत्या

» पुलिस हत्या या आत्महत्या में उलझी

» पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा इंतजार

» थाना प्रभारी बोले नहीं मिली है अभी तक कोई तहरीर

» बोले कई संगठनों के आ चुके हैं फोन

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बसेन गांव में एक दलित नवविवाहिता से दरिंदगी का मामला सामने आया है। जिसमें नवयुवती से सामूहिक गैंगरेप के बाद उसके गुप्तांगों के साथ दरिंदगी की गई। और बाद में गांव से बाहर एक किलोमीटर दूर हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया गया।

मृतका के परिजनों ने पुलिस में मामले की तहरीर दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

सोशल मीडिया में भी मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं थाना प्रभारी चौबेपुर ने बताया कि मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें तहरीर नहीं मिली है। वह दो दिनों से तहरीर का इंतजार के रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवयुवती के साथ सामूहिक दुराचार की बात कही जा रही है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है। कई फोन भी आ चुके हैं। घटना की रात 12 बजे तक मृतका अपनी बहनों के साथ बातें कर रही थी। फिर घटना किस समय हो गई। यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया की सुर्खियों में आया मामला, थानेदार बोले दो दिन से कर रहे तहरीर का इंतजार

गैंगरेप और हत्या जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में चौबेपुर पुलिस द्वारा घटना के 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज न करना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक ओर थाना प्रभारी तहरीर न मिलने की बात कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर मृतका के पिता की तहरीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं आशुतोष कठेरिया नाम के व्यक्ति द्वारा 17 जून को सुबह 9.57 बजे यूपी पुलिस को ट्वीट कर थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने

की शिकायत की है। जिसका स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है। साथ ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें एक युवक कह रहा है कि वह घटना की जानकारी करने के लिए उसे फोन जरूर करेगा। जिससे घटना की पुष्टि हो रही है। हालांकि स्वराज इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

महज तीन सप्ताह पहले हुआ था विवाह

गैंगरेप का शिकार हुई 19 वर्षीय नवविवाहिता का विवाह उसके बुआ के लड़के बजेड़ी थाना सौरिख छिबरामऊ निवासी निर्मल से हुआ था। बीते शनिवार को ही उसके मायके वाले ससुराल से लेकर गांव बसेन आए थे। सोमवार को उसका शव गांव से करीब एक किमी0 दूर पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने मामले की सूचना परिजनों को दी। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

आखिर मीडिया को क्यों गुमराह कर रही पुलिस

जिस तरह से गैंगरेप की घटना सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। पीड़ित पक्ष थाने में तहरीर दे चुका है। इसके बावजूद पुलिस एफआईआर न दर्ज करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना के दो दिन बीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। उससे पुलिस की भूमिका खुद शक के दायरे में आ गई है।

कानपुर: मनमानी और लापरवाही जिंदगी पर भारी

» कानपुर में गंगा नदी में डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

» अप्रैल से जून 2025 के बीच 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

» प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद लोग तय सीमा से आगे जाकर हादसे का शिकार हो रहे हैं.

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। **पानी से खिलवाड़ और हमारी लापरवाही जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है ये कानपुर में देखा जा सकता है। कानपुर में, जहां नदी में डूबने वालों की संख्या सबको डरा रही है. आंकड़ों की बात करें तो मात्र 78 दिनों के अंदर 22 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई है.**

गंगा नदी कानपुर से होकर भी गुजरती है. गंगा इस ऐतिहासिक शहर की लाइफलाइन भी है. साथ ही ये पर्यटन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. चाहे बात परिवार के साथ घूमने की हो या फिर किसी त्यौहार पर गंगा स्नान की, कानपुर के लोग हर मौके पर गंगा की गोद में पहुंच जाते हैं.

इन सबके बीच दिक्कत तब आती है जब इन्हीं में से कुछ लोग लापरवाही की हद पार कर देते हैं. कानपुर में गंगा के किनारे दर्जनों घाट हैं. इसके अलावा यहां का गंगा बैराज एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है. इसके साथ चेतावनी भी जुड़ी हुई है।

कानपुर के सभी घाटों और गंगा बैराज पर प्रशासन के सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति तय सीमा से आगे नहीं जाएगा. इसके अलावा कई जगहों पर पानी में जाने की बिल्कुल मनाही है.।

अनेकों चेतावनी और दर्जनों बोर्ड लगाने के बाद भी लोग गंगा के अंदर जाने से बाज नहीं आते. लगभग हर तीसरे दिन एक मौत हो रही है. ये आंकड़ा सबको डरा रहा है.

एडीएम एफ आर विवेक चतुर्वेदी के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से 17 जून, 2025 तक 22 लोगों की गंगा में डूबने से मौत हो चुकी है ।

जिनको मुआवजा भी दिया गया है. इतनी मौतें मात्र 74 दिनों के अंदर हुई हैं. इसमें से ज्यादातर मौतें गंगा में डूबने से हुई हैं.

कहां के कितने लोग हुए मौत का शिकार?

अगर हम तहसील की बात करें तो 22 मौतों में से 8 बिल्हौर तहसील में, 3 घाटमपुर में, 7 सदर और 4 मौतें नरवल तहसील में हुई हैं. इन सभी मामलों में मृतक नहाने गए हुए थे और चेतावनी बोर्ड के बावजूद गहरे पानी में चले गए. इसके बाद उनको बचाया नहीं जा सका.

प्रशासन की तरफ से एक बार फिर सभी को निर्देश दिए गए हैं

कि घाटों में सिर्फ वहीं तक जाएं जहां सुरक्षा जंजीर लगी है. उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा नदी में उतरने का प्रयास बिल्कुल ना करें. उन जगहों पर बिल्कुल ना जाएं जहां जाने की बिल्कुल मनाही है.।

नवचयनित सिपाहियों को मिले बेहतर प्रशिक्षण,अनुशासन और व्यवहार सिखाएं: एडीजी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। आप सभी को बताते चले कि कानपुर ज़ोन की धरती में तैनात ईमानदार छवि के तेजतर्रार, कड़क मज़ाज ,कर्तव्यनिस, न्यायप्रिय सीनियर आईपीएस अफसर एवं बहुचर्चित एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीआईजी कानपुर रेंज व डीआईजी झांसी रेंज एवं जोन के समस्त पुलिस अधीक्षकों के साथ जनपदों में आरक्षी ना0पु0 के पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत चयनित नवचयनित सिपाहियों के प्रशिक्षण,मूलभूत आवश्यकताओं एवं अन्य महत्वपूर्ण

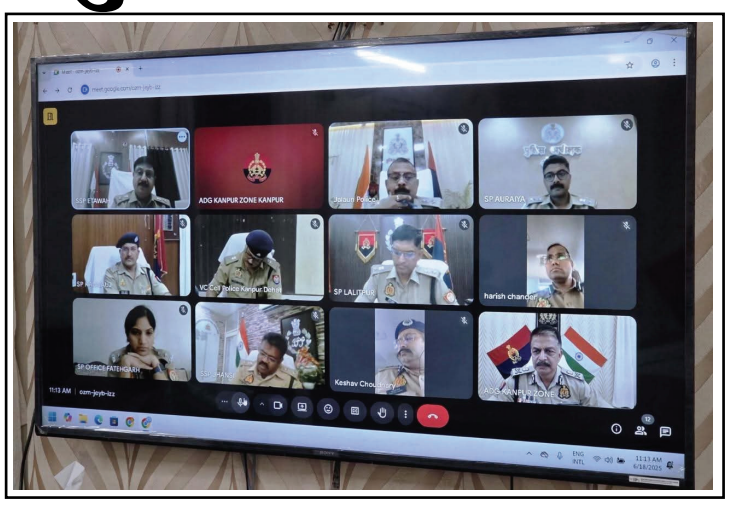

बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी।समीक्षा गोष्ठी के दौरान निर्देशित किया गया कि पुलिस मुख्यालय एवं इस कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरश :अनुपालन तथा सोशल मीडिया की गाइडलाइन के सम्बन्ध में नये नवचयनित सिपाहियों को अवश्य अवगत कराया

जाएं।एडीजी आलोक सिंह द्वारा जोनल कार्यायल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए जोर दिया.

50 से ज्यादा झोपड़ियों में लगी भीषण आग

धमाकों से दहला इलाका,खंभे से गिरी चिंगारी से हुआ हादसा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पनकी इलाके में 50 से ज्यादा झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। देर रात खंभे से गिरी चिंगारी से हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंचे दमकल के आठ वाहनों ने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में मंगलवार देर रात खंभे से गिरी चिंगारी के कारण सड़क किनारे की 50 से ज्यादा झोपड़ियां चपेट में आ गई। जब तक लोग फायर बिग्रेड पुलिस पुलिस को सूचना देते आग ने विकराल रूप ले लिया।सोते समय हुई घटना के कारण अफरातफरी मच गई। किसी तरह पीड़ितों ने अपने आशियाना से भागकर जान बचाई। झोपड़ियों में भीषण आग के कारण एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को काबू करने के प्रयास शुरू किए।

मिनटों में आग ने 50 झोपड़ियों को चपेट में ले लिया

पनकी के शताब्दी नगर रतनपुर में सड़क किनारे 50 से ज्यादा झोपड़ियों में सैकड़ों लोग गुजर बस करते हैं। रात करीब एक बजे बस्ती के ऊपर खंभे से निकली चिंगारी किसी झोपड़ी में पड़ी गई। मिनटों में झोपडी में लगी आग ने एक के बाद एक झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।

स्टोव और सिलेंडर फटने से हुए धमाके

आग लगने से लोग अपने गृहस्थी लेकर जान बचाकर भागे। झोपड़ियों के अंदर सो रहे बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। झोपडियों के अंदर रखे सिलेंडर और स्टोफ फटने से तेज धमाके हुए। आग की घटना से महकमे में हडकंप मच गया।

कई किमी तक दिखा भयावह नजारा

दमकल की छह गाड़ियां बस्ती के चारों तरफ से पानी डालकर आग बुझाने में लगी हैं। कई किमी तक से आग के भयावह नजारा साफ देखने लगे। आग से गरीबों की गृहस्थी जलने से बिलखने लगे। पनकी, अरमापुर, सचेंडी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा।

कोई जनहानि नहीं हुई है

मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। झोपड़ियों से सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है।

भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सीओडी पुल के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली। इस दौरान चालक मौके से फरार हो गया। गाड़ी में भारत सरकार लिखा है। चकेरी थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी रामकिशोर साहू (40) जरीबचौकी चौराहे पर स्थित एक प्लाईवुड की दुकान में काम करते थे। छोटे भाई श्यामू ने बताया कि वह रोज की तरह मंगलवार सुबह 10:30 बजे घर से ड्यूटी जाने के लिए निकले थे।

श्यामनगर के आगे सीओडी पुल पर चढ़ते ही रामादेवी की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इससे वह कुछ दूर घिसटते चले गए। भाई के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कि हेलमेट के टुकड़े सिर व चेहरे में घुस गए और उनकी मौके पर मौत /हो गई थी। मृतक की पत्नी गीता, बेटी दिव्यांशी और बेटे आयुष का रो रोकर हाल बेहाल है।चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि गाड़ी श्यामनगर गंगानगर निवासी लियाकत अली के नाम दर्ज है। गाड़ी चालक के बारे में पता किया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री गौरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED HOSPITAL)
यू.पी.एस.आई.डी.सी. जैनपुर, कानपुर देहात
Mob: 9710106661, 7310106662, 7310106663
अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन, डिजिटल एक्सरे की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध
- आई0सी0यू0/सी0सी0यू0।
- वेंटीलेटर, ए0वी0जी0ए0, कारडियक मॉनीटर, मल्टीपैरा मॉनीटर की सुविधा।
- C-Arm युक्त वतानुकूलित ऑपरेशन थियेटर।
- ट्रामा स्पोर्ट हेड इन्जुरी का सफल इलाज।
- डिजिटल एक्स.रे, सी.टी. स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड (U.S.G.) की सुविधा

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज उपलब्ध है।
टी.पी.ए. कैशलेस की सुविधा उपलब्ध
उपलब्ध सुविधाएंः– ए0बीजी0ए0 मशीन
1. अत्यंत कम वजन के नवजात शिशु एवं समय से पहले जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल। 2. नवजात एवं बाल्य गहन चिकित्सा इकाई ;च्ण्ब्ण्न्द्ध 3. चौबीस घंटे मेडिकल स्टोर, एक्सरे, पैथालॉजी, कैन्टीन की सुविधा। 4. नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। 5. दूरबीन द्वारा पित्त एवं गुर्दे, यूरेटर की पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। 6. गहन चिकित्सा इकाई, वेंटीलेटर सुविधा सहित। 7. सभी प्रकार के हड्डी रोग एवं ट्रामा सम्बंधित ऑपरेशन। 8. सिजेरियन ऑपरेशन/डिलेवरी/बच्चेदानी का ऑपरेशन अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर। 9. कार्डियक मीनीटरिंग/इको कार्डियोग्राफी/सोनोग्राफी/टी.एम.टी.
डा. संजय त्रिपाठी
एम.बी.बी.एस., एमडी मेडिसिन
फेलोशिप क्रिटिकल केयर
विजय बाजपेई
मैनेजिंग डायरेक्टर

स्वराज इंडिया

www.www.swarajindianews.com.com

वैचारिक मंच

05

कानपुर,बुधवार | 18 जून , 2025

सम्पादकीय

एसी पर नियंत्रण से आगे जाने की जरूरत

ऐसे वक्त में जब भारत के अनेक हिस्सों में तेज गर्मी से पारा उछल रहा है, तपिश से बचने के लिये बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि स्वाभाविक बात है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक गर्मी की तपिश से बचने के लिये कूलर से लेकर एसी तक का भरपूर इस्तेमाल करता है। हाल के दिनों में घरों, कार्यालयों, होटलों व मॉल तक में एसी का उपयोग बेतहाशा बढ़ा है। जिसके चलते गर्मियों के पीक सीजन में बिजली की खपत चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर यानी एसी की पहचान बिजली की बढ़ती खपत के लिये जिम्मेदार खलनायक के रूप में की है। केंद्र सरकार योजना बना रही है कि घरों,होटलों व कार्यालयों में बीस डिग्री से अट्ठाइस डिग्री सेल्सियस के बीच इस्तेमाल होने वाले इस उपकरण की कूलिंग रेंज को मानकीकृत किया जाए। नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद एसी निर्माताओं को बीस डिग्री से कम तापमान पर कूलिंग प्रदान करने वाले एसी बनाने से रोक दिया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार केंद्र सरकार की यह पहल बिजली बचाने और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस बात में दो राय नहीं कि गर्मियों की तपिश से बचने के लिये लोग अपने एसी को बहुत कम तापमान पर चलाते हैं। इस प्रवृत्ति का बिजली ग्रिड पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। निश्चित रूप से इसके चलते बिजली कटौती की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस संकट का अकेला मुख्य समाधान एसी को बेहद कम तापमान पर चलाया जाना ही नहीं है। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं। यह भी एक हकीकत है कि सरकारी व निजी कार्यालयों में एसी का उपयोग काफी लंबे समय तक अंधाधुंध ढंग से किया जाता है। यहां इसके उपयोग में किफायत बरतने की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। निस्संदेह, ऊर्जा मंत्रालय का ऊर्जा नियामक ब्यूरो, बिजली खपत कम करने वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है। लेकिन जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती बढ़ रही है तो तापमान बढ़ने पर बिजली की खपत अनिवार्य रूप से बढ़ने लगती है। लेकिन इसका एकमात्र कारण एसी का बढ़ता उपयोग ही नहीं है। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारे शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? हम इस बढ़ते तापमान से नागरिकों को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अंधाधुंध-अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे निर्माण कार्य भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। हमने चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तो बना दिए लेकिन शहरों में हरियाली का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। जिससे हवा का प्राकृतिक प्रवाह भी बाधित हो रहा है। विकास के नाम पर जो सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काटे जाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति नये पेड़ लगाकर नहीं की जाती है। हम घरों को प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाये रखने वाली भवन निर्माण तकनीक नहीं अपना रहे हैं। यदि उष्मारोधी भवन निर्माण सामग्री को बढ़ावा दिया जाए तो लोगों को कम बिजली खपत से भी राहत मिल सकती है। हमारी जीवनशैली बिजली की खपत को लगातार बढ़ा रही है। यदि हमारे देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए तो सड़कों पर निजी वाहनों का उपयोग कम होने से वाहनों के गर्मी बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।

साइप्रस से कूटनीतिक-आर्थिक संबंधों के निहितार्थ

पुष्परंजन

प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जून को ग्रीक-साइप्रस संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भारत यूरोपीय संघ के साथ एफटीए की तैयारी में है तो जब 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनेगा, तो संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी।

अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दक्षिणी दिल्ली की उस सड़क के नाम को सुधारा जायेगा। लोधी रोड के पीछे, पेड़ों से घिरा एक छोटा-सा रास्ता, जहां हरे रंग के एक बोर्ड पर हिंदी में लिखा है- 'आर्च बिशप माकोरियस मार्ग'। अंग्रेजी, गुरुमुखी, और उर्दू में भी वही लिखा है। दिल्ली स्थित साइप्रस उच्चायोग वालों का भी ध्यान दशकों से लगे इस बोर्ड पर नहीं गया। वास्तविक नाम है- 'आर्चबिशप मकारियोस तृतीय।' प्रधानमंत्री मोदी से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस सर्वोच्च सम्मान से नवाज़े जा चुके हैं। वर्ष 2017 में उन्हें यह पुरस्कार, साइप्रस की यात्रा के दौरान मिला, जहां उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस से मुलाकात की। यह पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया था।

वर्ष 2017 में साइप्रस गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का समर्थन किया। मगर, मकारियोस तृतीय के वास्तविक नाम से आठ साल तक दिल्ली वाले अनजान रहे। प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कार पर भी उनका नाम है, जिसने निकोसिया और नई दिल्ली के बीच एक ऐतिहासिक सूत्र को मजबूत किया था। वर्ष 1983 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में कई महत्वपूर्ण नेता आए थे, तब मुझे भी विदेश मंत्रालय में बहैसियत 'प्रोटोकॉल असिस्टेंट', काम करने का अवसर मिला था। दिल्ली आये जिन नेताओं को तब नज़दीक से देखने का अवसर मिला था, उनमें फिदेल कास्त्रो, यासिर अराफात भी शामिल थे। इसके बाद, कुछ चुनिंदा सड़कों को गुटनिरपेक्ष नेताओं के नाम रखा गया- 'जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग, गमाल अब्देल नासर मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग- और 'माकोरियस मार्ग'।

मकारियोस के नाम पर यह सड़क उस कूटनीतिक युग का अवशेष है, जो कभी बहुत चमकता था। बाद के दिनों में मनमोहन सरकार ने आर्चबिशप मकारियोस तृतीय की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। अब अचानक से आर्चबिशप मकारियोस तृतीय भारत में वायरल हो गए, जिन्होंने 1950 से 1977 तक साइप्रस के चर्च के आर्च बिशप के रूप में और 1960 और जुलाई, 1974 के बीच साइप्रस के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उसके प्रकारांतर, दिसंबर, 1974 और 1977 के बीच दूसरे कार्यकाल में भी वो शासन प्रमुख बने रहे। उन्हें साइप्रस गणराज्य के संस्थापक पिता, 'एथनार्क' के रूप में माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से इसके हस्तांतरण का नेतृत्व किया था। हालांकि, ब्रिटिश सरकार इस द्वीप को उपनिवेश मुक्त करने के लिए अनिच्छुक थी। ब्रिटिश गए भी, तो साइप्रस को भारत-पाकिस्तान की तरह बांटकर, और विवाद को रोपकर।ईओकेए बी एक ग्रीक साइप्रस अर्धसैनिक संगठन था, जिसे 1971 में जनरल जॉर्जियोस ग्रिवास ने अति राष्ट्रवादी विचारधाराओं के आधार पर बनाया था। इस संगठन का उद्देश्य साइप्रस को ग्रीस के साथ एकीकृत करना था, लेकिन बाद में नागरिकों पर हमलों के परिणामस्वरूप, साइप्रस गणराज्य द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर, एक आपराधिक संगठन माना गया था। आर्च बिशप मकारियोस एकमात्र यूरोपीय नेता थे, जिन्होंने अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित उपनिवेशवाद विरोधी 'बांडुंग सम्मेलन' में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया था। यह वह सम्मेलन था, जिसने अंततः गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जो अमेरिका और यूएसएसआर के नेतृत्व वाले शीतयुद्धीय शिविरों का विकल्प था। साइप्रस बेलग्रेड में 1961 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पच्चीस प्रतिभागियों में से एक था, जिसने औपचारिक रूप से आंदोलन की स्थापना की। 1957 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, भारत के विदेश मंत्री कृष्ण मेनन साइप्रस की स्वतंत्रता के पहले अधिवक्ताओं में से एक थे। मेनन ने साइप्रस की बिना शर्त स्वतंत्रता की वकालत की। आज, साइप्रस संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। तुर्की का प्रतिद्वंद्वी, जो सारे घोड़े खोल लेने के बाद भी यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं बन सका। साइप्रस 1 मई, 2004 को यूरोपीय संघ का सदस्य देश बना, 2026 में उसे ईयू का अध्यक्ष देश बनना है। इससे पहले 2012 में साइप्रस ईयू का अध्यक्ष देश बना था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जून, 2025 को ग्रीक-साइप्रस संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया। उन्हें इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। ज़ाहिर है, जब साइप्रस यूरोपीय संघ का अध्यक्ष देश बनेगा, भारत से संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा गश्त की जाने वाली उस ग्रीन लाइन का भी दौरा किया, जो राजधानी निकोसिया को दो भागों में विभाजित करती है। यह एर्दोआन को अखर रही होगी।सम्भव है, साइप्रस अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि अंकारा द्वारा इस्लामाबाद का समर्थन करने के बाद, तुर्की में भारतीय पर्यटकों की आमद में कमी आई थी, साथ ही भारतीयों ने तुर्की के उत्पादों और सेवाओं का भी बहिष्कार किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के ग्राउंड सर्विस प्रदाता सेलेबी के लिए सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी। भारत और साइप्रस के दोनों शिखर नेताओं ने सीमा पार लेन-देन के लिए साइप्रस में यूपीआई सेवाएं शुरू करने, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)।

हादसों की बढ़ती श्रृंखला और सुरक्षा की चूक

बोईंग खामियां

सुचिता खन्ना

बारह जून, 2025 दुनिया को इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। फिर 15 जून की उत्तराखंड में आर्यन एविएशन प्रा. लि. के एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने सवालों को और बड़ा कर दिया। शाम ढलने से पहले पुणे में बंद, जर्जर पुल तेज पानी के बहाव में उस पर खड़े बाढ़ का आनंद लेते लोगों का वजन नहीं सह पाया और ढह गया। इन हादसों ने सुरक्षा पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं।फ्लाइट एआई-171 के बोइंग की खूबियों के साथ खामियां पता थीं। इसकी तमाम सीरीज भी सुरक्षा पर घिरती रही। बोइंग पर सवार हजारों नॉटिकल मील के सफर पर निकले लोग, एक हथेली की पांच उंगलियों जितने मील भी नहीं उड़ पाए।पिछले साल अमेरिकी सीनेट ने बोइंग के पूर्व सीईओ डेव कॉलहम को सुरक्षा को लेकर कड़ी पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नए सीईओ केली ऑर्टबर्ग ने अगस्त 2024 में पद संभाला, लेकिन सुरक्षा चुनौतियां कम नहीं हुईं। जून, 2025 में ड्रीमलाइनर हादसे ने बोइंग पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जबकि पहले से ही सुरक्षा उल्लंघन और निरीक्षण में बाधा जैसे आरोप कंपनी पर लगे हुए थे।

आखिर बोइंग में ऐसी कौन-सी खराबी है जो दुर्घटनाएं थम नहीं रहीं? दुनिया में इसके पांच सबसे बड़े हादसों ने भरोसे को तोड़ा है। 1977 में टेनेरिफ हादसा हुआ। 2018 में लॉयन एयर फ्लाइट का बोइंग 737 मैक्स क्रैश से 189 मौतें हुईं। जबकि 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स में 157 और 2024 में जेजू एयर फ्लाइट के बोइंग 737-800 क्रैश में 179 लोगों की जान चली गई।

चिंताजनक यह है कि नई पीढ़ी के विमान मॉडल भी सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। बोइंग 737 सीरीज़ के 800 वैरिएंट ने पहली बार 1997 में उड़ान भरी और यह दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले तथा भरोसेमंद विमानों में गिना जाने लगा। इसकी शुरुआती यात्री क्षमता 189 थी। इसके बाद आए उन्नत संस्करण 'बोइंग 737 मैक्स' को बड़े इंजन, उन्नत मशीनरी और आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस किया गया था। लेकिन

डिजाइन संबंधी खामियों के चलते 2018 और 2019 में इसके दो विमानों की दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें कुल 346 लोगों की जान चली गई।

नए और उन्नत मॉडलों के बावजूद बोइंग पर लगातार सवाल उठते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंजीनियर सैम सालेहपुर के हवाले से बताया कि 787 ड्रीमलाइनर और 777 विमानों में खामियां हैं, जो शॉर्टकट्स की वजह से आई हैं और इससे बड़े हादसे हो सकते हैं। सैम ने कहा मकसद बोइंग को बदनाम करना नहीं, हादसों को रोकना है। उनकी चिंताओं को अनदेखा नहीं किया गया और 2021 में एफएए ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। बाद में बोइंग ने दुरुस्तियां कर डिलीवरी शुरू की, लेकिन कंपनी का दावा सुरक्षित होने का खोखला साबित हुआ। इसके चलते 737 मैक्स बेड़े की उड़ानों पर रोक लग गई। भारत के डीजीसीए ने भी 2019 से 2021 तक बोइंग 737 मैक्स विमानों को प्रतिबंधित रखा और 2024 में इमरजेंसी एग्जिट जांच के आदेश दिए। अमेरिका में भी 737 मैक्स 9 विमानों की उड़ानें रोक दी गईं।

अहमदाबाद दुर्घटना ने बोइंग विमानों की सुरक्षा पर फिर जबरदस्त चिंताएं बढ़ा दीं। पहले ही गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन की मजबूती, सुरक्षा मानकों और नियामक निगरानी पर सवाल कम नहीं हैं। वहीं, 2009 में पहले क्रैश के बाद से 100 से अधिक घटनाएं हुईं। साल की शुरुआत में ही वाशिंगटन जा रहे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को आइवरी कोस्ट पर उड़ते वक्त इमरजेंसी के चलते लागोस में लैंडिंग करानी पड़ी, सितंबर 2024 में, दिल्ली से बर्मिंघम जा रहे बोइंग 787-800 विमान की इमरजेंसी में मॉस्को में लैंडिंग कराई गई। 11 मार्च 2024 को 50 यात्रियों को लेकर सिडनी से ऑकलैंड जाते समय बोइंग ड्रीमलाइनर में अचानक हलचल हुई। यात्री छत से टकराए और कई घायल हो गए।2021 से 2023 के बीच, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए ने बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की डिलीवरी रोक दी ताकि सुरक्षा मानकों की जांच हो सके। उसके बाद बोइंग ने निर्माण प्रक्रिया में बदलाव कर डिलीवरी शुरू की। कंपनी ने कहा कि अब उसके विमान उड़ान के लिए सुरक्षित हैं। इस बीच फिटनेस और बाकी औपचारिकताओं को पूरा करने की कागजी कवायद में कोई कमी नहीं आई कि अहमदाबाद में इसी 12 जून को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश अब तक का तीसरा सबसे बड़ा हादसा बनकर सामने आया।

787 ड्रीमलाइनर साल 2011 में पहली बार सेवा में आया जिसने पिछले 14 साल तक बिना किसी घातक हादसे के 10 बिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से पहले इसके नाम कोई मौत दर्ज नहीं थी। लेकिन अहमदाबाद प्लेन क्रैश बोइंग का तीसरा सबसे बड़ा हादसा बन गया। बड़ा सवाल यह भी कि 108 साल पुरानी कंपनी, अनगिनत क्रैश और हजारों मौतों का कलंक क्या धुलेगा?

जिलाधिकारी सुबह ही चले गए लखनऊ, कांग्रेसियों ने कहा- आरोपों की हो जांच, हटाए जा सकते हैं सीएमओ

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के डीएम जेपी सिंह और सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के बीच विवाद शासन स्तर तक पहुंच गया है। मामले में शीघ्र समाधान ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि शीघ्र ही सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी हटाए जा सकते हैं।

कानपुर में डीएम-सीएमओ विवाद अब पांच कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। हालांकि सीएम के मंगलवार को राजधानी से बाहर होने की वजह से मामले का हल उनके आने के बाद ही पता चलेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मामले में तंज कसा है। एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर अलग अंदाज में टिप्पणी की।

कहा कि पहले इंजन लड़ते थे, अब डिब्बे भी लड़ने लगे हैं। उनका यह बयान भी खूब वायरल हो रहा है। इस बीच मंगलवार सुबह ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह शहर से बाहर चले गए। चर्चा है कि वह लखनऊ गए हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। माना जा रहा है कि वह इस मामले में प्रमुख सचिव के सामने अपनी बात रख सकते हैं।

कार्यों में लापरवाही के लिए हटाने की संस्तुति

उधर, सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी भी आज ड्यूटी पर नहीं गए। बताया गया कि उन्होंने आज के लिए छुट्टी ले रखी है। सीएमओ का कहना है कि उन्हें अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है। हालांकि डीएम ने उनके खिलाफ कार्यों में लापरवाही के लिए प्रमुख सचिव से उन्हें हटाने की संस्तुति की है। इस मामले को लेकर कुछ और जनप्रतिनिधि पत्र लिखकर धमाका करने की कोशिश में थे, लेकिन उनके संगठन ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया।

भाजपा संगठन ने मामले में साध रखी है चुप्पी

इधर, दूसरे दिन भी सोशल मीडिया से लेकर सरकारी विभागों के कार्यालयों में सिर्फ इसी मामले की चर्चा रही। जिन जनप्रतिनिधियों ने दोनों अधिकारियों का पक्ष लेते हुए पत्र लिखा था, वे दूसरे दिन ऊपर से तो शांत दिखे, लेकिन उनके पत्र के मुताबिक शासन का फैसला आए, इसके लिए कोशिश भी करते रहे। इससे अलग भाजपा संगठन ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। संगठन के लोगों का कहना है कि इसमें उनका पड़ना ठीक नहीं है। शहर के कुछ और प्रमुख लोग बिना आगे आए इस मसले में कमर कसे हुए हैं।

कांग्रेसियों ने ज्ञापन देकर कहा- आरोपों की हो जांच

कांग्रेस ग्रामीण इकाई के पदाधिकारियों ने मंगलवार को डीएम और सीएमओ के बीच जारी रस्साकसी की जांच की मांग संबंधी ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि अधिकारियों के बीच झगड़े से चिकित्सा विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले का संकेत मिल रहा है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व बार एसोसिएशन नरेश त्रिपाठी, सतीश दीक्षित, इखलाक अहमद डेविड आदि मौजूद रहे।

शासन में पहुंचा विवाद, हटाए जा सकते हैं सीएमओ

कानपुर के डीएम जेपी सिंह और सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के बीच विवाद शासन स्तर तक पहुंच गया है। मामले में शीघ्र समाधान ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि शीघ्र ही सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी हटाए जा सकते हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिस ऑडियो पर डीएम को आपत्ति है, उसकी जांच भी कराए जाने पर विचार चल रहा है। अगर यह सीएमओ की आवाज निकली तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी।

आरटीई में बदलाव बिना कैसे मर्ज होंगे सरकारी स्कूल ?

कम एडमिशन वाले प्राथमिक स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया को भले ही शुरू कर दिया हो लेकिन इसके बीच में विभाग की ओर से ही बनाया गया शिक्षा का अधिकार कानून आड़े आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस साल प्रदेश भर के हजारों सरकारी स्कूलों को बच्चों की कम संख्या के कारण पास के स्कूलों में मर्ज करने की योजना बनाई है जिसके लिए नियम बनाए गए हैं कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 25 से कम है उनको नजदीक के स्कूलों में मर्ज किया जाए। इसका जिम्मा विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा है लेकिन इस प्रक्रिया में आरटीई एक्ट बाधा बन गया है। आरटीई एक्ट में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और आरटीई अधिनियम 2009 के तहत हर गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात की गई थी तब यह सिर्फ एक सांख्यिकीय लक्ष्य नहीं था बल्कि एक संवैधानिक संकल्प था हर बच्चे को समान, सुलभ और सशक्त शिक्षा का अवसर देने का लेकिन आज जब शिक्षा तंत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, हर कक्षा में एक शिक्षक और शिक्षकों को शिक्षण में समर्पित रखने की होनी चाहिए थी तब हम एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। स्कूलों को मर्ज करने, पेयर करने और एकीकृत करने की प्रशासनिक कवायद शुरू की गई है। यह फैसला दरअसल असफलताओं का एक परोक्ष स्वीकृति-पत्र है जिसे न स्वीकारा गया, न सुधारा गया। जो प्रशासन आरटीई एक्ट लागू होने के डेढ़ दशक से भी अधिक समय में हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं दे सका, जो हर शिक्षक को चुनाव, जनगणना, राशन कार्ड, टीकाकरण, पोषण सर्वेक्षण और दर्जनों अन्य गैर-शिक्षण कार्यों से मुक्त नहीं कर सका, वह अब यह कह रहा है कि स्कूल तो बहुत हैं लेकिन शिक्षक कम हैं इसलिए स्कूलों को एकीकृत किया जायेगा। यह किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को ही बच्चों से छिपा देने की चाल है। स्कूल मर्जर का सीधा मतलब यह है कि कुछ स्कूल दिखाई तो देंगे लेकिन वहाँ ताले लटकेंगे और जहाँ बच्चे अभी पैदल 500 मीटर या 1 किलोमीटर में स्कूल पहुँच पा रहे हैं, अब उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर, ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर एक तथाकथित बेहतर स्कूल तक जाना होगा। यह विशेषकर प्राथमिक स्तर के बच्चों और बालिकाओं के लिए गहरी चिंता की बात है। यह सुविधा नहीं, शिक्षा से विमुखता की शुरुआत है। शिक्षाशास्त्र कहता है कि विद्यालय न केवल सीखने का स्थल है बल्कि वह समाज का सबसे निकटतम विश्वास केंद्र होता है। जब बच्चे अपने गांव में स्कूल के आँगन में सीखते हैं तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं रहती वह स्थानीयता, संस्कृति, भाषा और समुदाय से जुड़कर जीवंत बनती है। मर्जर इस जुड़ाव को तोड़ देता है। हम यह क्यों नहीं पूछते कि अगर शिक्षक कम हैं तो क्यों नहीं हर गांव के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, स्थायी नियुक्तियां देने और सेवा शर्तें बेहतर करने पर जोर दिया गया। हम यह क्यों नहीं पूछते कि क्यों न पहले शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्यों से मुक्त किया जाए ताकि वे अपने मूल कार्य पढ़ाने में पूरा समय दे सकें। सच्चाई यही है कि जो जिम्मेदार शिक्षक देने में विफल रहे, वही अब स्कूल ही छीनने पर आमादा हैं। यह नीति नहीं पलायन है। यह सुधार नहीं संविधान से छल है। बच्चों से यह दूरी न सिर्फ शिक्षा को दूर करती है बल्कि लोकतंत्र से उनका पहला रिश्ता स्थानीय स्कूल भी तोड़ देती है। अब वक्त आ गया है कि समाज, अभिभावक, शिक्षक और जागरूक नागरिक इस नीति के विरोध में खड़े हों और स्पष्ट कहें अपनी नाकामी की कीमत बच्चों की सुलभ शिक्षा से मत चुकाओ, अगर बेहतर नहीं कर सकते हो तो जो है उसे ही मत हटाओ।

डांस को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा पत्नी पहुंची रेलवे ट्रैक

» समोसा खाने के बाद फिर भड़की पत्नी, जान जोखिम में डाल रेलवे ट्रैक पर दौड़ी

» पति ने खींचकर बचाई जान, पुलिस ने कराया समझौता, फिर भी तनाव बरकरार

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के बिठूर क्षेत्र में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में डांस को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और पत्नी ने गुस्से में जान देने की कोशिश की।

घटना मंधना क्षेत्र की है। मंगलवार को जन्मदिन पार्टी के दौरान पत्नी करीब एक घंटे तक दूसरों के साथ डांस करती रही। जब पति ने एक युवती के साथ डांस करना शुरू किया, तो पत्नी भड़क गई और गुस्से में घर लौटकर पति से झगड़ने लगी। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसने पति को घर में पिटवाया और पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का समझौता करा दिया।

झगड़ा करने वाले दंपति की मां

बाद में दोनों ने साथ बैठकर केक और समोसे खाए। लेकिन समोसा खाने के बाद पत्नी फिर नाराज़ हो गई और गुस्से में मंधना की रेलवे पटरी की ओर दौड़ गई। उसी समय एक मालगाड़ी भी आ रही थी। पति पीछे दौड़ा और पत्नी को पटरी से खींचकर बाहर लाया, जिससे उसकी जान बच सकी।

नाराज़ बहू को समझाते परिजन

इस मामले में इंस्पेक्टर बिठूर प्रेमनारायण विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों के बीच समझौता कराया गया था। फिलहाल दंपति से पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

समस्या हेतु निस्तारण

समन्वय बैठक में सांसद रमेश अवस्थी बोले

मंडल अध्यक्षों को थाना दिवसों पर बुलाया जाए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर की समस्याओं से पुलिस को रूबरू कराने और उनके निस्तारण के लिए भाजपा मंडल अध्यक्षों को थाना दिवस पर बुलाने के लिए सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से कहा है। मंगलवार को वह सीपी कार्यालय में जिलाध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों के साथ समन्वय बैठक कर रहे थे।इस दौरान दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने किदवई नगर के साकेत नगर, कंजरन पुरवा, गुजैनी में वरुण बिहार कच्ची बस्ती और बर्रा आठ में देशी शराब ठेके के सामने खुले आम स्मैक, चरस, अफीम, गांजा सहित कई तरह के मादक पदार्थों की बिक्री का मामला उठाया। बताया कि इस रैकेट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

उन्होंने नौबस्ता चौराहे पर अवैध टैक्सी, टैंपो स्टैंड का भी मुद्दा उठाया। इसी तरह उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कल्याणपुर और डबल पुलिया में पेट्रोल पंप के पीछे अवैध बस्ती में खुले आम मादक पदार्थों की बिक्री होने की शिकायत की। इस मौके पर बिट्टू परिहार, दीपू पासवान, दीपांकर मिश्रा, सनी जायसवाल, ओपी आर्या, सुमित तिवारी, विनीत दुबे, सुमित पावा, विजय पटेल मौजूद रहे।

तेल से भरा टैंकर पलटा, हादसा टला

» हादसे में मां और बेटे बुरी तरह झुलस गए

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के मीरापुर गांव में मेंथा आयल की टंकी फटने से एक हादसा हो गया। इस हादसे में मां और बेटे बुरी तरह झुलस गए। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की है। 30 वर्षीय सुमन और उनका 12 वर्षीय बेटा आदित्य मेंथा मिल की टंकी की झुकाई व देखभाल कर रहे थे। इसी दौरान अचानक टंकी फट गई। टंकी में भरा खौलता पानी मां-बेटे पर गिर गया।

हादसे में आदित्य करीब 80 प्रतिशत जल गया। उसकी मां सुमन भी 50 प्रतिशत से अधिक झुलस गईं। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।घायलों को पहले संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।आदित्य के बाबा हनुमान ने बताया कि सुबह मेंथा आयल निकालने के लिए टंकी में पिपरमेंट भरकर प्रक्रिया शुरू की गई थी। तेल निकलना शुरू होने के बाद वे खेत चले गए थे। इसी बीच यह हादसा हो गया।

सरयू नदी के संजय सेतु में आई दरार से हड़कंप

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। सरयू नदी के संजय सेतु में आई दरारों का मरम्मतीकरण कार्य मंगलवार की सुबह से शुरू हुआ है। जिसके मद्देनजर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया और छोटे वाहनों को वनसाइड निकाला गया। विभागीय कर्मचारियों द्वारा तीन दिनो तक यह कार्य किया जाएगा। ज्ञात हो लखनऊ बहराइच हाईवे स्थित सरयू नदी पर बना पुल मरम्मत के सहारे भारी वाहनों का भार झेल रहा है। हाल ही में पुल के अप्रोचों को भरने का कार्य किया गया था लेकिन चंद दिनो में पुन: ज्याइंटो में दरारें आ गयी जिन्हें सुधारने का कार्य मंगलवार की सुबह दस से शाम चार बजे तक विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया। इस दौरान लखनऊ से गोण्डा जाने वाले भारी वाहनों को फतेहपुर व बदोसराय मार्ग पर रूट डायवर्जन रहा। थाना रामनगर की पुलिस पुलिस के द्वारा पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर छोटे वाहनों को वन साइड निकाला गया। पुल के अप्रोचो के मरम्मतीकरण कार्य बृहस्पतिवार तक चलेगा।

शव दफनाने को लेकर दो समुदायों में तनाव

» राजस्व और पुलिस की टीम ने दोनो पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

निंदुरा (बाराबंकी)। शव दफनाने को लेकर दो समुदायों में तनाव की स्थिति बन गई सूचना के बाद पहुंचे राजस्व और पुलिस की टीम में दोनो पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करते हुए मृतक की निजी जमीन में उसका अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। मंगलवार को फतेहपुर तहसील क्षेत्र के सराय भीख गांव निवासी गुरुदीन 40 पुत्र जानकी की कैंसर बीमारी के चलते मौत हो गई। परिजनों ने गांव के पास ही स्थित कब्रिस्तान की गाटा संख्या 70 पर गुरूदीन का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो गाँव के ही मखदूम,कम्मल आदि ने अपने धर्म का कब्रिस्तान बताकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मामले की सूचना पर पहुचें एसडीएम कार्तिकेय सिंह व सीओ जगतराम कनौजिया ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया। जिसके बाद गुरूदीन के परिजनों ने अपनी निजी जमीन पर अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। कई घंटे चले विवाद के बाद देर शाम को प्रशासन की मौजूदगी मे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि शव दफनाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद था दोनों पक्षों से वार्ता कर मामले को शांत कराया गया। जिसके बाद परिजन अपनी निजी जमीन पर मृतक का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। मौके पर स्थित सामान्य है। इस दौरान नायब तहसीलदार अभिनव सिंह,थानाध्यक्ष मनोज कुमार, लेखपाल दीपक कुमार वर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक:** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर 6000 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

» जिला प्रशासन की पहल से मसाला, गारमेंट, प्लास्टिक, और लेदर उद्योगों में बढ़ा महिला सहभागिता

» राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को मिला स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती का रास्ता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 की विशेष पहल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में 40 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) सक्रिय हैं, जिनमें से 6 सीएलएफ के माध्यम से लगभग 6000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं मसाला निर्माण, होजरी, लेदर प्रोडक्ट, और प्लास्टिक सामान निर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रही हैं। विकास खंड अकबरपुर की प्रेरणा महिला समिति द्वारा प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, ग्राम पंचायत अकोडी (मलासा) की महिलाओं द्वारा कढ़ाई-कार्य युक्त परिधानों का निर्माण, और जैनपुर (सरवनखेड़ा) की महिलाओं द्वारा लेदर प्रोडक्ट निर्माण कार्य में सक्रिय भागीदारी की जा रही है।इसके अलावा मसाला उद्योग में कार्य हेतु मड़वई और कुईतमंदिर की महिलाओं को कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वहीं, उमंग और जाग्रति महिला समूह द्वारा गारमेंट्स एवं जम्बो बैग निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिल रही है।

जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

» सड़क की गुणवत्ता, मोटाई और जल निकासी की व्यवस्था की गहन जांच

» निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह ने आज लोक निर्माण विभाग द्वारा 5 करोड़ से अधिक लागत से बन रही सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने चांदपुर मलासा देवीपुर कैलई बरौर बलिहारामऊ मार्ग और बढ़ौली-मुंगीसापुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों का जायज़ा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क की मोटाई, निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था की गहन जांच कर अधिशाषी अभियंता को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को उच्च गुणवत्ता की आधारभूत सुविधाएं समय पर मिलें। इस हेतु अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता राजेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियंता हेमन्त कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी जितेन्द्र कटियार, सहायक अभियंता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दो साल से रिंग रोड की बाधा बनी जमीन पर गरजा बुलडोजर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। छतमरा और टिगरा गांव की नौ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे थे। दो साल किसानों को मनाने का प्रयास चल रहा था। चौगुना मुआवजे की मांग कर रहे थे।

दो साल से रिंग रोड के तीसरे चरण के निर्माण में बाधा बन रही छतमरा और टिगरा पैगंबर गांव की जमीन मंगलवार को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा ली। रिंग रोड के लिए 1.800 किलोमीटर लंबाई में चयनित भूमि पर बने निर्माणों और खड़ी फसल पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा।

इस दौरान महिलाओं और किसानों ने काफी विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की न चली। भूमि का समतलीकरण होने के बाद कंपनी ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 93.20 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना रिंग रोड के पैकेज-एक में सचेंडी से मंधना व पैकेज-चार में रमईपुर से सचेंडी और पैकेज तीन में रमईपुर से आटा तक का निर्माण कार्य चल रहा है। पैकेज तीन में नर्वल तहसील के छतमरा और टिगरा पैगंबर गांव की नौ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का करीब 40 से अधिक किसान विरोध कर रहे थे। बीते दो साल से उन्हें मनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा था। किसान सर्किल रेट का चौगुना मुआवजा देने की मांग पर अड़े थे। किसानों को सरकार दोगुना मुआवजा दे रही थी। इसमें करीब 80 से अधिक किसान पहले मुआवजा ले चुके थे।

कुछ किसानों के चक्कर में रिंग रोड का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। शासन स्तर से लगातार जमीन अधिग्रहित करने पर जोर दिया जा रहा था। इस मामले की जानकारी डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को दी गई। उन्होंने शासन स्तर पर चर्चा की। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एडीएम भूमि संतोष कुमार, एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा, नायब तहसीलदार आशीष पटेल व एनएचएआई अधिकारियों की टीम मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंची। चारों तरफ पुलिस ने पहरा लगा दिया। इसके बाद जमीन पर खड़ी बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। यह देख गांव के किसान और महिलाएं विरोध करने पहुंच गए।

(स्वराज इंडिया अयोध्या विशेष कवर स्टोरी)

स्वास्थ विभाग में उपकरणों की खरीद में करोड़ों घपलेबाजी

» अयोध्या में 6 करोड़ की लूट का पर्दाफाश

» श्रीराम की नगरी में मरीजों के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट

» जिला अस्पताल की अलमारियों में धूल फांक रहे करोड़ों के मेडिकल उपकरण

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। जिला चिकित्सालय अयोध्या में 'स्वास्थ्य सेवा सुधार' के नाम पर करोड़ों की सरकारी धनराशि खर्च तो हुई, लेकिन उसका न तो कोई उपयोग हुआ, न प्रशिक्षण दिया गया और न ही जवाबदेही तय की गई। कुल ?6,09,67,442 की लागत से खरीदे गए तमाम आधुनिक चिकित्सा उपकरण या तो शुरू से खराब निकले या फिर इस्तेमाल होने से पहले ही गोदामों में ठूंस दिए गए। आंकड़ों और फाइलों में दर्ज इन मशीनों ने किसी मरीज का जीवन नहीं बचाया, लेकिन कुछ जेबों की गर्मी जरूर बढ़ा दी।

वेन फाइंडर से लेकर हीमोग्लोबिन मीटर तक – सब शोपीस बने बैठे हैं! जिन उपकरणों को खरीदकर अस्पताल की छवि सुधारनी थी, वे अब सरकारी लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। वेन फाइंडर, जो नसों को खोजने के लिए है कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इजी चेक हीमोग्लोबिन मीटर जिसके लिए जरूरी स्ट्रिप्स ही नहीं मंगाई गईं।कुछ उपकरण ऐसे भी खरीदे गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी सिर्फ बजट खपाने के लिए!

मंत्री बदलते रहे, माफिया यथावत रहे

यह 'खरीद कांड' डॉ. बृज कुमार और डॉ. विपिन वर्मा के कार्यकाल में हुआ। लाखों–करोड़ों के उपकरण खरीदे गए, कंपनियों से सप्लाई ली गई, लेकिन न टेस्टिंग हुई, न एएमसी, न ही कोई जवाबदेही तय हुई। घोटाले की शिकायत हुई, जांच की बात भी चली – लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। दोषियों को हटा तो दिया गया, पर सज़ा नहीं मिली।

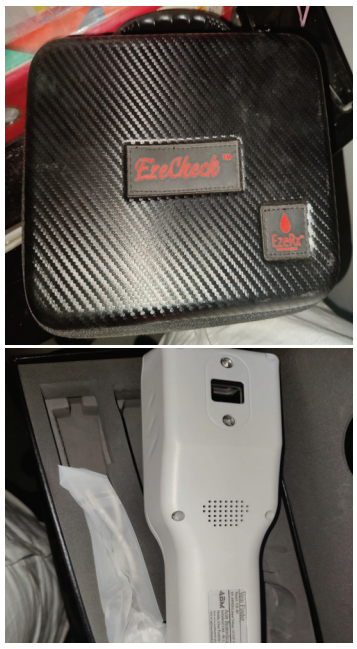

अयोध्या स्वास्थ्य विभाग में धूल फांक रहे करोड़ों रुपए के उपकरण

अफसर की चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति

यदि उपकरण खरीदे गए हैं तो उनका उपयोग होना चाहिए। यह मेरे कार्यकाल की खरीद नहीं है। हो सकता है और भी ऐसे कई उपकरण हों जो उपयोग में नहीं आ रहे हों।

ए.के. सिन्हा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक

स्वराज इंडिया की पड़ताल में खुलासा ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सिस्टमेटिक लूट है!

सिर्फ कागजों में उपयोग, जमीन पर जीरो। मरीज इलाज के लिए लाइन में खड़े रहे और मशीनें आलमारी में बंद पड़ी रहीं। यह सीधे-सीधे जनता के पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि सुनियोजित सरकारी लूट है।

स्वराज इंडिया का सवाल -

-कब जागेगा स्वास्थ्य मंत्रालय?

-क्या अब भी दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी?

-क्या उपकरणों का इस्तेमाल सुनिश्चित होगा या अगले बजट तक फिर नई खरीद होगी?-क्या मरीजों के नाम पर ऐसे खेलों को रोकने का कोई सिस्टम बनेगा?

स्वराज इंडिया की निगाह इस मामले पर बनी हुई है। हम अगली कड़ी में बताएंगे कि किस कंपनी को कितने का भुगतान हुआ, किसने किस उपकरण पर हस्ताक्षर किए और कौन अब भी कुर्सी पर बैठा है।

दोस्ती के नाम पर कत्ल...

शव को हाईवे से फेंक भागे आरोपी, तीन गिरफ्तार

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या।जनपद अयोध्या के थाना रौनाही क्षेत्र के ग्राम जगनपुर में मिली युवक की लावारिस लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के इस सनसनीखेज मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो मृतक के परिचित निकले। हत्या का कारण रुपयों का विवाद बताया जा रहा है।

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवन्त चौधरी और सीओ सदर योगेन्द्र कुमार की निगरानी में प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव की टीम ने तीनों आरोपियों—अश्वनी सिंह उर्फ मिर्ची, नसीम उर्फ छोटू कटरा और आकिब कुरैशी—को आल्टो कार सहित गिरफ्तार किया।

13 जून को की गई थी हत्या, 14 जून को मिला था शव

पुलिस के अनुसार, मृतक साहिल पुत्र साबिर निवासी मडियांव, लखनऊ, 13 जून को अपने परिचित अश्वनी सिंह से मिलने लखनऊ के जानकीपुरम गया था। वहीं पर रुपयों के लेनदेन को लेकर उसका विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अगले दिन शव को आल्टो कार में लादकर अयोध्या के जगनपुर गांव लाकर फेंक दिया गया।

वीडियो बना अहम सुराग, सीसीटीवी व सर्विलांस से खुला राज

पुलिस को जब शव की पहचान नहीं हो सकी तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद मृतक के भाई आमिर ने शव की शिनाख्त साहिल के रूप में की और रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में

अश्वनी के मोबाइल से एक वीडियो मिला, जिसमें साहिल के साथ मारपीट होती दिख रही है। मुखबिर की सूचना पर 17 जून की रात तीनों आरोपियों को बेगमगंज रोड पर 8ः10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अश्वनी सिंह उर्फ मिर्ची, निवासी जानकीपुरम, लखनऊ,नसीम उर्फ छोटू कटरा, निवासी मडियांव, लखनऊ,आकिब कुरैशी, निवासी हुसैनाबाद, लखनऊ (मूलतः बाराबंकी) निवासी शामिल है।

2026 के पंचायत चुनाव में छिपा है 2027 का जनादेश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सबसे अहम सियासी इम्तिहान पंचायत चुनाव होगा, जिसे सूबे की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन चुनावों की तैयारी ने अभी से पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से साफ हो गया है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या अब 57,695 रह गई है। वर्ष 2021 में ये संख्या 58,199 थी, यानी इस बार 504 पंचायतें कम हो गई हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रदेश में तेजी से हुए शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शहरी सीमाओं के विस्तार के चलते कई ग्राम पंचायतें अब नगर निकायों में शामिल हो गई हैं। इससे कई जिलों में पंचायतों की संख्या घट गई है। देवरिया में सबसे अधिक 64 ग्राम पंचायतों का विलय हुआ है, इसके बाद आजमगढ़ में 47, प्रतापगढ़ में 45, अमरोहा और गोरखपुर में 21-21 पंचायतें कम हुई हैं। गाजियाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर जैसे अन्य जिलों में भी यही स्थिति देखने को मिली है।

» पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या अब 57,695 रह गई

» इस बड़े बदलाव के पीछे प्रदेश में तेजी से हुए शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है

पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में कराए जाने की संभावना है। इस बार 57,695 ग्राम प्रधान, 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। यह चुनाव न केवल ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों का जनाधार भी तय करेंगे। यही कारण है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी इस बार सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, तो वहीं विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस चुनाव को 2027 की लड़ाई की बुनियाद मान रही है।

अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार

सबसे बड़ी बहस इस समय पंचायत चुनावों में सुधार को लेकर हो रही है। कई दलों की मांग है कि अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे जनता से कराए जाएं, जैसे ग्राम प्रधानों का चुनाव होता है। अभी तक यह चुनाव पंचायत समिति या जिला पंचायत सदस्यों द्वारा होता आया है, जिससे भारी भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और एनडीए के भीतर से भी ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता इन पदों पर डायरेक्ट इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और संभवतः इसे लागू करने के लिए विधानमंडल में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

भाजपा इन चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रही: सपा

राजनीतिक तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा इन चुनावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा सीसीटीवी और डेटा एनालिटिक्स के जरिए मतदाताओं की निगरानी कर रही है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सीसीटीवी में पकड़े जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा के भरोसे लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए कितनी भी अनैतिक तकनीक और रणनीति क्यों न अपनानी पड़े।

अखिलेश यादव ने अपनी PD (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नीति को भी आगे बढ़ाते हुए पंचायत चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुख बनाया है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन एक ﬂभावनात्मक गठबंधन है, जो उन सभी के लिए है जो समाज में हाशिए पर हैं। उन्होंने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय का आधार बताया और कहा कि सपा इसके पूर्ण समर्थन में है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह चेतावनी भी दी कि जनगणना के आंकड़ों में किसी भी तरह की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर बेहद सतर्क

वहीं भाजपा भी पंचायत चुनाव को लेकर बेहद सतर्क है। वह जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए ﬂ वर्ग के बीच कैम्पेन चला रही है। भाजपा यह बताने की कोशिश कर रही है कि पिछली सरकारों ने मंडल आयोग और काका कलेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू न करके पिछड़ों के साथ अन्याय किया। भाजपा अब इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए जातीय जागरूकता अभियान चला रही है और पंचायत चुनाव के जरिए इस समर्थन को मजबूती देने की तैयारी में है।

पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच कांग्रेस का रुख भी साफ हो चुका है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी और ÒINDIAÓ ब्लॉक की भावना के अनुरूप सभी क्षेत्रीय दलों के साथ समन्वय बनाकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने यहां तक कहा कि अगला चुनाव केवल भाजपा के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि यह चुनाव आयोग और संपूर्ण चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता की लड़ाई भी होगा।

उन्होंने पंचायत चुनाव में AI और डाटा निगरानी जैसे प्रयोगों पर चिंता जताई और कहा कि इससे लोकतंत्र को गंभीर खतरा है।

पंचायत चुनावों के समानांतर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्राथमिक स्कूलों की जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इंटरमीडिएट कॉलेजों की हालत खराब है, और सरकार की निगाह केवल उनकी जमीनों पर है। यह टिप्पणी ग्रामीण मतदाताओं को सीधे संबोधित करती है, जिनके बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा, अखिलेश ने बदायूं में पटेल समाज के साथ हुए कथित अन्याय का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि समाजवादी पार्टी इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश और विदेश भेजे गए मजदूरों के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और पूछा कि ऐसे मामलों में आज तक किसी मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ।

इन तमाम राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपों, नीतिगत परिवर्तनों और तकनीकी प्रयोगों के बीच पंचायत चुनाव अब केवल स्थानीय निकाय का चुनाव न होकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला यथार्थ बन चुका है। यह चुनाव सामाजिक न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल नैतिकता और राजनीतिक गठबंधन की परिपक्वता की असली परीक्षा होगी।

2026 में होने वाला यह चुनाव चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, लेकिन इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव तक गूंजता रहेगा।

यही वजह है कि सभी दल अभी से अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं और इस बार पंचायत चुनाव महज ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासी दिशा का जनादेश बनता नजर आ रहा है।

अयोध्या जिला अस्पताल या अराजकता की मंडी?

» अयोध्या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स या दलाल–पहचाने कैसे?

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। यह जिला अस्पताल है या बिचौलियों का अखाड़ा–यह सवाल आजकल हर उस तीमारदार की जुबान पर है, जो मरीज लेकर अयोध्या के जिला चिकित्सालय पहुंचता है। कारण? अस्पताल में तैनात डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी अपनी पहचान छिपाए घूम रहे हैं। न ड्रेस कोड, न नेमप्लेट, न कोई जवाबदेही–और इस अराजकता का फायदा उठा रहे हैं वही लोग, जो 'मरीज की मजबूरी' को अपना धंधा बना चुके हैं।ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक हर गेट, हर कोने पर एक ही सवाल गूंजता है- कौन है असली डॉक्टर और कौन है ब्लड माफिया या दवा दलाल? नाम-पहचान छुपाकर काम करने वाले ये स्वास्थ्यकर्मी मरीजों से अवैध वसूली कर रहे हैं। कोई ब्लड दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है, तो कोई डॉक्टर से मिलवा देंगे कहकर जेब काट लेता है। गले में लटकती पहचान पट्टियां और ड्यूटी ड्रेस अगर होती, तो शायद यह सारा झोल न हो पाता।

डॉ एके सिन्हा सीएमएस

अस्पताल के अंदर मरीजों की पहचान जितनी आसान है, स्टाफ की पहचान उतनी ही मुश्किल। अफरातफरी का आलम ऐसा कि तीमारदारों को कई बार दलालों के हाथों इलाज का सौदा करना पड़ता है। डॉक्टर और नर्स, अगर यूनिफॉर्म में होते तो जिम्मेदारी तय होती। लेकिन जब कोई भी किसी को कुछ भी कह दे वाला माहौल हो, तो भ्रष्टाचार को कौन रोके?

प्रशासन की चुप्पी–सबसे बड़ी बीमारी

प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। न कोई निरीक्षण, न चेतावनी, न ही सख्ती। नतीजा–सफेद कोट की जगह सफेद झूठ चल रहा है। जनता अब सवाल कर रही है–क्या यह सरकारी अस्पताल है या दलालों की मंडी?

समाधान? जवाबदेही तय कीजिए!

-सभी डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड लागू हो

-गले में पहचान-पत्र की अनिवार्यता तय हो

-ओपीडी और इमरजेंसी में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए

-दलालों की पहचान कर अस्पताल से बाहर किया जाए

जब तक अस्पताल के भीतर स्टाफ और स्ट्रीट स्मार्ट दलालों की पहचान साफ नहीं होगी, तब तक इलाज नहीं–शिकार मिलेगा मरीजों को।

ड्रेस न पहनने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही–सीएमएस

जब इस सम्बंध में सीएमएस डॉ ए के सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने कहा की सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को ड्रेस में रहने का लिखित आदेश कई बार जारी किया गया है लेकिन अगर वह इसका पालन नही कर रहे है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

हड़कंप : पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर 92 फीसदी घटा

भारत द्वारा सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और जल आपूर्ति प्रभावित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने का असर अब साफ नजर आने लगा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से घट गया है, जिससे वहां की सिंचाई और जल आपूर्ति प्रणाली पर गंभीर असर पड़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, 29 मई को चिनाब नदी का फ्लो 98,200 क्यूसेक दर्ज किया गया था। लेकिन भारत द्वारा जल प्रवाह रोके जाने के बाद यह घटकर मात्र 7,200 क्यूसेक रह गया है-यानी लगभग 92 फीसदी की भारी कमी। भारत ने यह कदम 24 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार करते हुए पाकिस्तान को जाने वाले जल प्रवाह पर रोक लगाने का फैसला किया।

क्या है सिंधु जल समझौता? : 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल वितरण को लेकर बना था। इसमें भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग और पाकिस्तान को शेष तीन नदियों का अधिकार दिया गया था। भारत का यह कदम न केवल पाकिस्तान के लिए जल संकट का कारण बन रहा है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल मचा रहा है। पाकिस्तान में अब चिनाब के सूखते किनारों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं भारत में इस कदम को सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के नजरिए से देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान अभी सूखे का दंश झेल रहा है, वहीं पाकिस्तान की इंडस वाटर रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून आने पर देश भर में बाढ़ आ सकती है। अथॉरिटी का कहना है कि मानसून की वजह से भारत अपने सभी डैम से पानी छोड़ सकता है, जिससे नदियों में पानी का स्तर सामान्य लेवल से बढ़ सकता है।

डेड जोन में चिनाब नदी, फसलें बर्बाद

पाकिस्तान को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद चिनाब नदी का जल प्रवाह 92 फीसदी तक कम हो गया है, जिससे देश की 40 फीसदी फसल नष्ट हो चुकी है। पंजाब और सिंध प्रांतों के 6.5 करोड़ लोग इस संकट से प्रभावित हैं, जबकि किसानों को 2200 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना अब महंगा पड़ने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे देश में पानी की भारी किल्लत हो रही है। देश की 40 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसान रो रहे हैं. दावा है कि पानी की कमी से 2000 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा का नुकसान हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो कई किसान संगठनों ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। ऐसे में पाकिस्तानी लोग सड़कों पर आ रही है।

पाकिस्तान में बचा है सिर्फ 35 दिन का पानी

भारत द्वारा सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किए जाने का प्रभाव पाकिस्तान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल संकट गहराता जा रहा है। खानपुर डैम में जल स्तर तेजी से घट रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में डैम में बचा पानी केवल 35 दिनों तक की जरूरतें ही पूरी कर पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि अगले 10 से 15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जलाशय के कई हिस्सों में चट्टानें और टीले दिखाई देने लगे हैं। वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार (7 मई) को डैम का जल स्तर 1,935 फीट (AMSL) दर्ज किया गया, जो डेड लेवल 1,910 फीट से केवल 25 फीट ऊपर है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कम बारिश और सूखे की वजह से जलग्रहण क्षेत्र के प्राकृतिक झरने भी सूख चुके हैं।

ट्रंप को मोदी की दो टूक

अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध की तरह देखता है भारत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और साफ किया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को पाकिस्तान के अनुरोध के बाद रोका गया था। इसमें अमेरिका की मध्यस्थता या व्यापार सौदे की पेशकश जैसी कोई वजह नहीं थी। पिछले महीने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद ट्रंप और मोदी के बीच यह पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर बात की।

इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की ओर से शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में जानकारी दी और साफ किया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं देखेगा, वह से युद्ध कार्रवाई की तरह देखता है।

मोदी-ट्रंप फोन कॉल के बारे में विदेश सचिव ने क्या कहा? : विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी-ट्रंप फोन कॉल पर एक बयान में कहा, 'पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में व्यापार से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा।'

उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जी-7 बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए पीएम मोदी को कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने का निमंत्रण दिया।

बंद घर में किया हाथ साफ

नकदी और डेढ़ करोड़ के जेवरात चुरा ले गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर तीन में खरगपुर जागीर गांव के पूर्व प्रधान ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा रहते हैं। उनके घर के बगल में ही उनके भतीजे दुर्गेश कुमार मिश्रा व राम मनोहर मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों भाई मिलकर 60 फिट रोड पर पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं। पीड़ित दुर्गेश ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य 28 मई को बैंगलोर में अपनी बहन के घर गए हुए थे। 21 दिन बाद मंगलवार रात सभी घर वापस आए तब उन्हें चोरी होने का पता चला।

बर्थ-डे गिफ्ट में दोस्त को दी डांसर

रातभर की थी दरिंदगी, गाड़ी नंबर से हुई पहचान, चार्जशीट दाखिल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोरखपुर। कुशीनगर डांसर दुष्कर्म मामले में जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रामकोला इलाके में दो डांसर के साथ दरिंदगी हुई थी। एक डॉक्टर के साथ पांच आरोपी हैं।

गोरखपुर में डांसरों को असलहे के बल पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में हुई दरिंदगी के इस मामले में गोरखपुर के डॉ. विवेक सेठ, बरही कोठी निवासी आर्थक सिंह, कृष तिवारी, अस्वन सिंह और नागेंद्र यादव और कुशीनगर के अजीत सिंह को आरोपी बनाया गया है।

दुष्कर्म और अपहरण का केस दर्ज

डांसरों के अपहरण होने की सूचना के बाद पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई थी। जिनके मकान में डांसर रहती थीं, उन्होंने रामकोला पुलिस को सूचना दी और गाड़ी का नंबर भी बताया। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने उसके मालिक का पता किया। इसी तरह गाड़ी की पहचान हो गई थी। इसके बाद आरोपियों को दुष्कर्म और अपहरण का केस दर्ज किया गया।

तीन को मिल चुकी जमानत

गीडा क्षेत्र के एकला बांध पर पंजाब की दो डांसरों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों (कर्मवीर निषाद, सोनू निषाद और संत कुमार) को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दो आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

घटना, आठ सितंबर 2024 की है। रामकोला थाना क्षेत्र के एक चौराहे पर स्थित मकान में पश्चिम बंगाल निवासी दो डांसर रहती थीं। आरोप है कि रविवार देर रात करीब 11:30 बजे दो लग्जरी वाहनों से छह लोग पहुंचे और जबरन डांसरों के कमरे में घुस गए। असलहा निकालकर हवाई फायरिंग करते हुए डांसरों को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। पड़ोसी ने बीच-बचाव की कोशिश की तो मनबढ़ों ने उनके साथ मारपीट की। रास्तेभर मनबढ़ों ने हवाई फायरिंग करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद कसानगंज थाना क्षेत्र में एक मकान में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा ने बताया कि घटना के कुछ दिनों के भीतर ही पुलिस ने जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। मामला अब न्यायालय में है।